



म्यूच्युअल फंड हेतु सेबी के नए नियम

चर्चा में क्यों?

नविशकों के हितों की रक्षा करने के लिये भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India -SEBI) ऐसे सभी म्यूच्युअल फंड के वरिद्ध कार्यवाही करेगा जिसमें डफिॉल्ट होने वाली कंपनी के प्रवर्तकों को शेयर के बदले ऋण दिया गया हो। इसके अतिरिक्त SEBI ने म्यूच्युअल फंड हाउसेस (MF houses) के लिये कुछ नए और सख्त नविश मापदंडों को भी मंजूरी दी है।

मुख्य बढि

- वशिषज्जों के अनुसार SEBI द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य उधारकर्त्ताओं के डफिॉल्ट हो जाने की स्थितिमें उत्पन्न होने वाले ऋण जोखमि से नविशकों की रक्षा करना है।
- वर्तमान में म्यूच्युअल फंड उद्योग एक भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है जिसके लिये उन फंड प्रबंधकों को ज़मिमेदार ठहराया गया है जो ऋण योजनाओं के माध्यम से कंपनी प्रवर्तकों को उधार देते हैं।
- 'फंड हाउस' (fund houses) ने कंपनी प्रवर्तकों के साथ ऐसे समझौते किये हैं जिनके अनुसार, 'डफिॉल्ट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी वे कंपनी के अंशों को किसी एक नश्चिति समय तक बेंच नहीं सकते हैं।'
- परन्तु SEBI ने ऐसे किसी भी समझौते को मान्यता नहीं दी है।
- SEBI के अनुसार म्यूच्युअल फंड बैंक नहीं होते हैं इसलिये उन्हें ऋण देने के बजाय बाज़ार में नविश करना चाहिये।

कौन होता है प्रमोटर या प्रवर्तक?

- प्रवर्तक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कंपनी के प्रवर्तन के बारे में कार्य करते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि वियापार/कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति को ही प्रवर्तक कहते हैं।

नए नविश मापदंड

- म्यूच्युअल फंड अब केवल सूचीबद्ध ऋण या इक्विटी (Debt or Equity) में ही नविश कर सकते हैं।
- नए मापदंडों के अनुसार अब से जोखमि की गणना परशिोधन (Amortisation) के आधार पर नहीं बल्कि मार्क-टू-मार्केट (mark-to-market) आधार पर की जाएगी।
- किसी भी म्यूच्युअल फंड को ऋण में नविश करने के लिये चार गुना कवर प्रदान करना होगा और इसे इक्विटी द्वारा भी सुरक्षा प्रदान करनी होगी।
- इसके अतिरिक्त तरल म्यूच्युअल फंड योजनाओं (MF Liquid Schemes) को अपनी कुल नविश परसिंपत्तिका 20 प्रतिशत हिस्सा नकद या गलिट फंड के रूप में बनाए रखना होगा, जो उन्हें प्रतदान/शोधन/मोचन (Redemptions) में मदद कर सकता है।

90

भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड

(Securities and Exchange Board of India)

- भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।

■ इसके मुख्य कार्य हैं -

- प्रतभूतियों (securities) में नविश करने वाले नविशकों के हतियों का संरक्षण करना ।
- प्रतभूतबाज़ार (securities market) के वकिस का उन्नयन करना तथा उसे वनियमति करना और उससे संबधति या उसके आनुषंगकि वषियों का प्रावधान करना ।

स्रोत: द हट्टू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sebi-tightens-norms-for-mfs>